आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 01.10.2023 समय : 0705

<><><><><><><><>

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर आज सुबह दस बजे देशभर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।
- द्वीपसमूह के एक हजार से अधिक स्थानों पर स्वच्छता के लिए लोग श्रमदान करेंगे।
- निकोबार ज़िला प्रशासन की ओर से हाल ही में चौरा और तेरेसा द्वीप में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- सूचीबद्ध बैंकों में जाकर दो हजार का नोट जमा करने या बदलने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर सात अक्तूबर कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह कल टैगोर कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ।

<><><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर आज देशभर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे महात्मा गांधी को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि देने के लिए आज सुबह दस बजे एक घंटे के लिए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। बीते रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस स्वच्छता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि स्वच्छता की यह कार्यांजलि महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के छह लाख चालीस हजार से अधिक स्थलों पर श्रमदान किया जाएगा। द्वीपसमूह में भी ग्राम

पंचायत से लेकर वार्डों तक एक हजार से अधिक स्थानों पर स्वच्छता के लिए लोग श्रमदान करेंगे। सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार, जल निकायों, पर्यटक स्थलों, तट और अन्य क्षेत्रों में होने वाली साफ–सफाई में बडी संख्या में लोग भाग लेंगे। सफाई स्थलों पर, लोग अपनी तस्वीरें खींच कर इसे swachhatahiseva.com पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

<><><><><><><>

निकोबार ज़िला प्रशासन की ओर से हाल ही में चौरा और तेरेसा द्वीप में एक दिवसीय प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। ननकौड़ी के सहायक आयुक्त अनुज कुमार भारती की अगुवाई में एक दल ने इन स्थानों पर पहुंचकर कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य लोगों को उनके घरों तक जरूरी सेवाएं उपलब्ध करवाना था। इस दौरान स्थानीय लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और उनके शिकायतों को सुना गया। कई मुद्दों का मौके पर ही समाधान भी किया गया। सहायक आयुक्त ने लोगों को शिकायतों का जल्द समाधान करने को लेकर आश्वस्त किया। लोगों ने विभिन्न प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने के लिए कमोर्टा तक सफर करने में आने वाली चुनौतियों को अधिकारियों के समक्ष रखा। बताया गया कि इन द्वीपों में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने की संभावनाओं का आंकलन किया जा चुका है और जल्द ही दोनों द्वीपों में ई–कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। इससे लोगों को आवश्यक सेवाओं के लिए कमोर्टा तक नहीं जाना पड़ेगा। ई–कॉर्नर बनाने से पहले आवेदन जमा करने के लिए एक अस्थाई व्यवस्था बनाई गई है। लोग अपने क्षेत्र के ए एस आर ओ के पास आवेदन जमा कर सकते है, जहां से इन्हें प्रमाणपत्र

बनाने के लिए कमोर्टा भेजा जाएगा। प्रमाणपत्र जारी करने के बाद वितरण के लिए इन्हें ए एस आर ओ के पास वापस भेज दिया जाएगा।

<><><><><><><><><>

इस दौरान दोनों स्थानों पर नब्बे आय प्रमाणपत्र, स्थानीय और जनजाति प्रमाणपत्र भी जारी किए गए। साढ़े तीन सौ से अधिक आधार कार्ड में सुधार और पंजीकरण का काम भी किया गया। जनजाति नेताओं ने आधार कार्ड पंजीकरण और इसमें सुधार की सेवा जारी रखने की मांग की। दोनों द्वीपों में आधार से जुड़ी सेवा प्रदान करने का आश्वासन भी दिया गया। जिला उपायुक्त ज्योति कुमारी के नेतृत्व में इस शिविर का आयोजन किया गया।

<><><><><><><><><>

सूचीबद्ध बैंकों में जाकर दो हजार का नोट जमा करने या बदलने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर सात अक्तूबर कर दिया गया है। दो हजार का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी समीक्षा के उपरांत कल इसकी घोषणा की। आर.बी.आई ने बताया कि चलन में रहे छियानब्बे प्रतिशत दो हजार के नोट वापस आ चुके हैं। सात अक्तूबर के बाद लोग आर.बी.आई के उन्नीस क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर अपने नोट जमा कर सकते हैं या इन्हें बदलवा सकते हैं।

<><><><><><><><><>

राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह कल मिडिल प्वाइंट स्थित टैगोर कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण निदेशक डॉ. नितिन शाक्या मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने मोटे अनाज के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सामाज

कल्याण विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में माताएं भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्याकर्ताओं द्वारा स्वागत गीत और लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। मुख्य सेविका शीला कार ने पोषण माह के दौरान की गई गतिविधियों पर जानकारी दी। कार्यक्रम में बच्चों ने शास्त्रीय नृत्य भी प्रस्तुत किए। मोटें अनाज से बने व्यंजनों तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध फल–सब्जियों और स्वदेशी खिलौनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।

<><><><><><><><><><>

नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से द्वीपसमूह में अक्टूबर माह के दौरान विशेष आधार शिविर आयोजित किए जाएंगे। तीनों जिलों की ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकार आधार से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह शिविर तीन अक्टूबर से आरंभ होकर इक्कतीस अक्टूबर तक चलेंगे। तीन अक्टूबर को ग्राम पंचायत मीठाखाड़ी, नमूनाघर और वी के पुर में शिविर लगेगा। यह शिविर सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर शाम साढ़े चार बजे तक चलेंगे। लोगों से इन शिविरों का लाभ उठाने की अपील की गई है।

<><><><><><><><><><>

आज से पोर्ट ब्लेयर–लौंग आईलैंड के बीच दैनिक फेरी सेवा शुरू होने जा रही है। यह फेरी स्वराज द्वीप होते हुए लौंग आईलैंड जाएगी। फेरी सुबह आठ बजे पोर्ट ब्लेयर से छूटेगी और दस बजकर पन्द्रह मिनट पर स्वराज द्वीप पहुंचेगी। स्वराज द्वीप से सुबह साढ़े दस बजे फेरी लौंग आइलैंड के लिए रवाना होगी। वापसी में यह फेरी लौंग आईलैंड से दोपहर बारह बजकर पैंतालीस मिनट पर छूटेगी

और दो बजकर पैंतालीस मिनट पर स्वराज द्वीप पहुंचेगी। स्वराज द्वीप से तीन बजे यह फेरी रवाना होगी और शाम पांच बजकर पन्द्रह मिनट पर पोर्ट ब्लेयर पंहुचेगी। इस फेरी सेवा के शुरू होने से पोर्ट ब्लेयर–लौंग आईलैंड से जुड़ेगा और रोज़ाना आने–जाने वाले स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटको को भी सुविधा मिलेगा। लौंग आईलैंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

<><><><><><><>

बाईसवें विधि आयोग ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र को बरकरार रखने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसे कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। भारत में सहमति की वर्तमान आयु अटठारह वर्ष है। इसमें यह भी कहा गया है कि उन मामलों में स्थिति का समाधान करने के लिए पॉक्सो अधिनियम में कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता है, जहां सोलह से अटठारह वर्ष की आयु के बच्चे की ओर से कानून में सहमति नहीं बल्कि मौन स्वीकृति है। यह राय दी गई कि ऐसे मामलों को उतनी गंभीरता से नहीं निपटाया जाना चाहिए जितना कि उन मामलों को माना जाता है, जिन्हें आदर्श रूप से पॉक्सो अधिनियम के तहत लाने की कल्पना की गई थी। आयोग ने इस महीने की सत्ताईस तारीख को कानून मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

<><><><><><><>